

मैक्रो वीक 2024 में वक्तव्य*

श्री शक्तिकान्त दास

आज पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) द्वारा आयोजित मैक्रो वीक 2024 में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। संस्थान ने खुद को एक ऐसे अग्रणी मंच के रूप में स्थापित किया है जो उभरते व्यापक आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए लोक नीति से जुड़े व्यवसायियों, केंद्रीय बैंकों, उद्योग जगत के नेताओं, अनुसंधान पेशेवरों और विद्वानों को एक साथ लाता है। इस तरह की चर्चाएँ, जो विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान हो रही हों, समकालीन नीतिगत प्रासंगिकता के मामलों पर गहनतापूर्वक और सार्थक बातचीत के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं।

आज अपने वक्तव्य में मैं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कार्यसूची और आर्थिक तथा वित्तीय विखंडन से जूझ रही दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर अपने कुछ विचार साझा करूंगा। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि जलवायु परिवर्तन को केंद्रीय बैंक की विचारधारा का हिस्सा क्यों और कैसे होना चाहिए।

1. अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कार्यसूची

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं, जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, भू-आर्थिक बदलावों, पर्यावरणीय चुनौतियों और वर्तमान में चल रहे वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों जैसी शक्तियों द्वारा संचालित हैं। इस तेजी से बदलते दौर में, जी20 और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों पर वैश्विक स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए तेजी से अनुकूलन और निर्णायक रूप से कार्य करने का दायित्व है। मैं इस संदर्भ में छह प्राथमिकता क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिनका क्रम कोई माइने नहीं रखता।

पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना स्वरूप में सुधार** को दी जानी चाहिए। इसमें ऐसे समावेशी वैश्विक अभिशासन ढांचे को प्राथमिकता देना शामिल है जो आज

की वैश्विक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। मौजूदा प्रणाली में, हालांकि आधारभूत है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समान स्तर और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए खुद को सुधारने की जरूरत है। संसाधनों तक बेहतर पहुंच और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों के अभिशासन में एक मजबूत भूमिका न केवल इन संस्थानों का महत्व बढ़ाएगी बल्कि व्यापक वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में अधिक गंभीर वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

दूसरा, कार्यसूची में **ऋण पुनर्गठन तंत्र** होना चाहिए। हालांकि जी20 की डेट सर्विस सस्पेंशन इनीशिएटिव (डीएसएसआई) और कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट सराहनीय उपाय थे, किंतु समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है। ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाएँ तदर्थ, धीमी और कई मौकों पर पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं रहती हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक चलने वाले संकटों में होता है, जिससे ऋणी देशों को अनावश्यक आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। हमें ऋण समाधान संरचना में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और इसे ऐसे रूप में ढालना चाहिए जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के ऋणदाता शामिल हों, समय पर ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित हो और ऋण राहत को सतत विकास उद्देश्यों से जोड़ा जा सके। इस तरह के सुधार के बिना, कमजोर देशों को असहनीय ऋण बोझ का सामना करना पड़ेगा जिसका वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तीसरा, हमें वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, संस्थानों और बाजारों दोनों की कमजोरियों और कमियों को पहचानना चाहिए। हाल के वर्षों में उन्नत और उभरते बाजारों, दोनों में वित्तीय अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम सामने आए हैं। निजी पूंजी और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए **वैश्विक वित्तीय विनियमन में सुधार** करने की वास्तव में बहुत जरूरत है, जिनकी अब वैश्विक आस्तियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। शेडो बैंकिंग और फिनटेक का उदय, और विकेंद्रीकृत वित्त के बढ़ते पदचिह्नों से होने वाले संक्रामक प्रभावों को रोकने और वैश्विक सार्वजनिक हित के रूप में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक मजबूत विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता है।

* पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (पीआईआईई) द्वारा आयोजित मैक्रो वीक 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का संबोधन, 25 अक्टूबर 2024, वाशिंगटन डीसी।

डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड) चिंता का चौथा क्षेत्र है। जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक डिजिटल होती जा रही है, डिजिटल समावेशन के लिए बुनियादी ढांचे, कौशल और विनियामक ढाँचों की कमी वाले देशों के और पीछे छूटने का जोखिम है। जी20 और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय संस्थानों को एक ऐसे पारितंत्र को पोषित करने की दिशा में काम करना चाहिए जो साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा दे।

पाँचवाँ, भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक नीतियों को तेज़ी से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण प्रतिबंध, वित्त का शस्त्रीकरण, व्यापार प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान हो रहे हैं। यह **आर्थिक विखंडन** का कारण बन रहा है, क्योंकि देश ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी रणनीतिक सामग्री वाले प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते हैं। जी20 को खुले और नियम-आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देकर आर्थिक विखंडन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देशों द्वारा अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, जी20 को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक सार्वजनिक हितों में निवेश और हरित संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

छठा है **जलवायु वित्त**, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह जी20 की प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय कार्यसूची में सबसे आगे होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण को निधि देने के लिए काफी अधिक संसाधन जुटाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जी20 को राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय भी करना चाहिए ताकि जलवायु नीतियों से संरक्षणवाद, एकतरफा व्यापार बाधाएँ या व्यापार संघर्ष न हों। अनावश्यक आर्थिक विखंडन से बचने के लिए सीमा कार्बन समायोजन (बीसीए) और इसी तरह के उपायों के उदय को सहकारिता के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे नवीन वित्तीय साधनों की तत्काल आवश्यकता है जो जलवायु संबंधी प्रयासों में निजी पूंजी को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। जब तक हम जलवायु वित्त को संबोधित करने के अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के तरीके में मौलिक बदलाव नहीं लाते हैं, पर्यावरणीय हास और वैश्विक असमानता बढ़ने का जोखिम बना रहेगा।

हम अत्यधिक अनिश्चितता और उथल-पुथल के युग में रह रहे हैं, जहाँ नीति निर्माताओं का काम अशांत समुद्र के माध्यम से गुजर रहे एक विशाल, परस्पर जुड़े बेड़ों को चलाने जैसा है, जहाँ पुरानी कार्यपद्धति अब पर्याप्त नहीं प्रतीत होती। वृद्धिशील परिवर्तनों का समय अब चला गया है। अब जिस बात की ज़रूरत है वह एक परिवर्तनकारी प्रयास जो यह सुनिश्चित करे कि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था सभी देशों और लोगों के लिए हो न कि केवल कुछ चुनिंदा देशों अथवा लोगों के लिए। सामूहिक कार्रवाई और बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ, हम एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में 21वीं सदी के लिए उपयुक्त होगी।

II. आर्थिक और वित्तीय विखंडन

वैश्विक सहयोग और विशेष रूप से वैश्विक बाजारों का एकीकरण, दशकों तक विश्व विकास को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। कई कम आय वाले देशों और उभरते बाजारों के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह एकीकरण उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है। इसने उन्हें किफायती आयात, व्यापक निर्यात बाजारों और विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की। लेकिन, अब भू-आर्थिक विखंडन वैश्विक विकास के दृष्टिकोण पर बाधा साबित हो रहा है।¹ व्यापार निर्बंधनों और वित्तीय प्रतिबंधों में वृद्धि होने से 2024 में भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक² (दी जिओपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स) तेज़ी से बढ़ा है। इससे वैश्विक आर्थिक एकीकरण से मिलने वाले बड़े लाभों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।³ अब वि-वैश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण बढ़ने की आशंकाएँ हैं। यह उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर जीवन स्तर के समीप आने की गति को धीमा कर सकती हैं। भू-राजनीतिक जोखिम पूंजी प्रवाह और आस्ति कीमतों में भी अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। वे वैश्विक भुगतान प्रणालियों की दक्षता को भी कम कर रहे हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से माल, सेवाओं और पूंजी के सीमा पार प्रवाह में आगे कोई सुधार नहीं हुआ है। हाल की

¹ अगस्त 2023 में आईएमएफ स्टाफ द्वारा किया गया एक अध्ययन यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध की अवधि अधिक लंबी होने से वैश्विक आर्थिक उत्पादन 7 प्रतिशत तक घट सकता है, जो आज के डॉलर के रूप में लगभग 7.4 ट्रिलियन यूएसडी राशि हो सकती है। यह फ्रांस और जर्मन अर्थव्यवस्थाओं के संयुक्त आकार के बराबर है, और उप-सहारा अफ्रीका के वार्षिक उत्पादन का तीन गुना है (दी आई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकॉनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, आईएमएफ ब्लॉग, अगस्त 2023)।

² कैलडारा, डारियो और इकोविप्लो, मैटेओ (2022), "मेजरिंग जिओपॉलिटिकल रिस्क", अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, खंड 112, संख्या 4, अप्रैल, पृष्ठ 1194-1225।

³ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, जून 2024।

भू-राजनीतिक घटनाओं ने व्यापार और रसद व्यवधानों में वृद्धि के साथ-साथ संरक्षणवाद को और बढ़ावा दिया है⁴। वि-वैश्वीकरण के कारण कम आय वाले कई देशों और उभरते बाजारों के लिए संभावित नुकसान बहुत अधिक हो सकते हैं। इन नकारात्मक जोखिमों के बावजूद, हाल के अनुमान उत्साहजनक हैं जो बताते हैं कि वैश्विक माल व्यापार में इस वर्ष 2.7 से 3.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी⁵। भले ही यह निकट अवधि की समुत्थानशीलता आशा का एक स्रोत हो, लेकिन बढ़ते अनिश्चित समय के लिए तैयारी करते हुए बदलती परिस्थितियों के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण है।

हाल ही में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भू-राजनीतिक घटनाओं और महामारी तथा जलवायु संकट जैसे व्यापक मुद्दों के कारण बड़े व्यवधान भी देखे गए। इससे विकास के चालक के रूप में जीवीसी की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। 'फ्रेंड-शोरिंग' और 'रीशोरिंग' के बारे में चर्चाएँ विदेशी प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण उपायों की असंगति और भय फैला रही हैं। ऐसे व्यापार वातावरण में, जो इसमें शामिल नहीं हैं वे असमान रूप से प्रभावित होंगे।

विखंडन के अन्य रूप - जैसे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एकरूपता का न होना और बाधित पूंजी प्रवाह - भी अपने प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और लागत बढ़ाएंगे। वे बैंकों और घरेलू वित्तीय संस्थानों की वित्तपोषण लागत को भी प्रभावित कर सकते हैं, उनकी लाभप्रदता को कम कर सकते हैं, और उन्हें आर्थिक गतिविधि पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऋण देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों के भीतर पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय भंडार के साथ-साथ पूंजी और चलनिधि बफर का निर्माण करना उभरती अर्थव्यवस्थाओं की इस तरह के प्रतिकूल बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अंत में, यह आशंका है कि यदि भू-आर्थिक विखंडन निरंतर जारी रहता है, तो देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बुनियादी ढांचे और वैश्विक मानकों पर कम निर्भर होने की कोशिश कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के विखंडन से बाजारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अंतर-संचालन की कमी वाली

नई समानांतर प्रणालियाँ उभर सकती हैं, जिससे लेनदेन लागत और अन्य अक्षमताएँ बढ़ सकती हैं। ऐसे तनावों और अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए संकट की तैयारी को मजबूत करना उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। देशों के बीच आपसी समझौतों के माध्यम से वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें रीजनल सेफ्टी नेट, मुद्रा स्वैप, राजकोषीय तंत्र और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से एहतियाती ऋण व्यवस्था शामिल हो सकती हैं। अगर ये व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने सेफ्टी नेट और बफर को काफी हद तक बढ़ाना होगा।

III. केंद्रीय बैंकिंग और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन नीति पर पारंपरिक दृष्टिकोणों ने चरम जलवायु घटनाओं से होने वाले परिणामों से निपटने के लिए अधिक अद्यतन बहु-नियामक दृष्टिकोण का मार्ग उपलब्ध कराया है। मांग-आपूर्ति आघातों, उत्पादकता हानि, आर्स्टि पुनर्मूल्यांकन और उच्च लागत पर कम कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण के माध्यम से इन जोखिमों के उभरने से वित्तीय, मौद्रिक और मूल्य स्थिरता बिगड़ सकती है⁶। मेरे विचार से, सवाल यह नहीं है कि केंद्रीय बैंकों को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इस विचार को उनके केंद्रीय अधिदेशों में किस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में शामिल उच्च लागत और अन्य संक्रमण जोखिमों को देखते हुए मूल्य स्थिरता पर प्रभाव को समझना शामिल है⁷। दूसरा, वित्तीय स्थिरता पर इसके सभी प्रकार के प्रभावों का आकलन करना महत्वपूर्ण है⁸। तीसरा, वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े भौतिक जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सूक्ष्म विवेकपूर्ण जिम्मेदारियों⁹ को संतुलित करना आवश्यक है। चौथा, इस क्षेत्र में

⁶ जलवायु परिवर्तन विषय अब वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की कार्यसूची में प्रमुख मद है। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस), जिसे 2017 में आठ केंद्रीय बैंकों की पहल पर स्थापित किया गया था, में अब 141 सदस्य और 21 पर्यवेक्षक शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक अथवा प्रतिनिधि प्राधिकरण शामिल हैं।

⁷ मोनिटरी पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज - की टेकअवेज प्रॉम दी मेंबरशिप सर्वे एंड एरियाज फॉर फरदर एनालिसिस, जुलाई 2023 - एनजीएफएस।

⁸ वित्तीय स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, 2020।

⁹ प्रिंसिपल्स फॉर दी इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ क्लाइमेट-रिलेटेड फिनान्शियल रिस्क, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस), 2022।

⁴ अध्याय 1, जिओइकॉनोमिक फ्रेगमेंटेशन: दी इकॉनोमिक रिस्क प्रॉम ए फ्रेक्चर्ड वर्ल्ड इकॉनोमी। सीईपीआर और आईएमएफ, 2023।

⁵ ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, डब्ल्यूटीओ, अक्टूबर 2024 और वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, आईएमएफ, अक्टूबर 2024।

जागरूकता और विचार नेतृत्व¹⁰ को सक्षम करने के लिए मजबूत विश्लेषण और शोध की आवश्यकता है¹¹।

जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कोई स्पष्ट दायित्व नहीं है। यह इसके व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता अधिदेशों से प्राप्त एक अनुमानित जिम्मेदारी है। इसने उपयुक्त साधनों और कार्रवाई योग्य ढाँचों को पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के भीतर एक स्थायी वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की है और 2021 में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) में भी शामिल हो गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से उठाए गए कुछ कदमों में हरित वित्त पहलों को बढ़ावा देना शामिल है जैसे कि बैंकों द्वारा निर्देशित ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना; सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना; 'ग्रीन डिपॉजिट' की स्वीकृति के लिए एक ढाँचा स्थापित करना; और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढाँचा विकसित करना और जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन करना।

राष्ट्र स्तर पर, मेरा मानना है कि जलवायु-संबंधी जोखिमों से निपटने के दौरान केंद्रीय बैंकों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को उचित रूप में विचार में लेना महत्वपूर्ण है। एक ओर केंद्रीय बैंकों को अपने विशिष्ट कानूनी ढाँचे के दायरे में काम करना पड़ता है और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह संस्थाओं के रूप में, उन्हें अपने सभी कार्यों के समर्थन में ठोस सबूत देने पड़ते हैं। दूसरी ओर, यह संभावना हो सकती है कि केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र पर पहले से ही जलवायु-संबंधी जोखिमों का असर पड़ा हो बाद में उन्हें उनका निराकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावी संस्था सरकार है, प्रत्येक देश

¹⁰ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने जलवायु संबंधी कार्यों पर काम करने के लिए समर्पित केंद्रीय बैंक इकाइयाँ बनाई हैं।

¹¹ मई 2021 में, रिज़र्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और सतत वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में विनियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए बैंक के भीतर एक टिकाऊ वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की।

को अपनी घरेलू परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना होगा- कि केंद्रीय बैंक के लिए स्पष्ट जलवायु अधिदेश रखा जाए या इसे अपने मूल्य और वित्तीय स्थिरता अधिदेश में शामिल किया जाए।

IV. निष्कर्ष

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं संक्षेप में भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यापक आर्थिक अनुभव पर बात करना चाहूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण निर्मित गंभीर संकुचन से उबर गई है और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है। चालू वर्ष (2024-25) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें इस पूर्वानुमान के आसपास जोखिमों को समान रूप से संतुलित रखा गया है। घरेलू मांग में सुधार, कम इनपुट लागत और एक सहायक नीतिगत माहौल¹², विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। संवृद्धि दृष्टिकोण भारत के वृहद-बुनियादी सिद्धांतों की अंतर्निहित ताकत को दर्शाता है, जिसमें घरेलू चालक अर्थात् निजी खपत और निवेश - प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर और बैंकों और कॉरपोरेट्स के स्वस्थ तुलन-पत्र से निजी निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है। निजी खपत, जो कुल मांग का मुख्य आधार है, अनुकूल कृषि दृष्टिकोण और ग्रामीण मांग में तेजी के कारण मजबूत सुधार के लिए अपने मार्ग पर है। सेवाओं में निरंतर प्रगति से शहरी मांग को भी समर्थन मिलेगा।

लचीली संवृद्धि ने हमें मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया है, ताकि इसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक स्थायी रूप से कम किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही से हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी आने का अनुमान है। अप्रत्याशित मौसमी घटनाएं और भू-राजनीतिक संघर्षों का और गंभीर होना मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

¹² उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) [3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए विस्तारित], प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) [चरण IV का शुभारंभ], राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसी सरकारी योजनाएँ पूंजी निर्माण को गति प्रदान करेंगी।

वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना रिज़र्व बैंक की निरंतर प्राथमिकता रही है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्वास्थ्य मानदंड अब बहुत मजबूत हैं। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा प्राप्त वाले क्षेत्रों में निरंतर ऋण प्रवाह हुआ है जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा था, आज, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती की तस्वीर

पेश करती है। मुद्रास्फीति और संवृद्धि के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है। बाह्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था की ताकत दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार नए शिखर छू रहा है। राजकोषीय समेकन चल रहा है। वित्तीय क्षेत्र मजबूत और समुत्थानशील बना हुआ है। भारत की संभावनाओं में वैश्विक निवेशक आशावाद शायद अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इन सबके बावजूद हम आत्मसंतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।

धन्यवाद।